बिना संस्कार नहीं सहकार

बिना सहकार नहीं उद्धार

छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार

वर्ष- 23 अंक - 11 सितंबर 2026 प्रथम पाक्षिक RNI NO. CHHHIN/2012/45105 प्रकाशन तिथि 15 सितंबर पृष्ठ-12 मूल्य 2000/- वार्षिक

नारी शक्ति और युवा नवाचार से बनेगा नया छत्तीसगढ़ : राज्यपाल डेका

- **सीएसवीटीयू भिलाई का बीआईटी दुर्ग में 'महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं स्टार्टअप अभिनंदन कार्यक्रम'**
- **कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल**

रायपुर। छत्तीसगढ़ (सीएसवीटीयू) भिलाई द्वारा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), दुर्ग परिसर में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं स्टार्टअप अभिनंदन कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुलाधिपति एवं प्रदेश् के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने 72 महिला स्व-सहायता-समूहों को मिलेट हेल्थ कार्ट और 24 स्टार्टअप्स को इग्निशन ग्रांट वितरण किया। समारोह में सांसद श्री विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, दुर्ग महापौर श्रीमती अल्का बाघमार और सहकार भारती के श्री कनीराम शर्मा भी सम्मिलित हुए।

तकनीकी ज्ञान तभी सार्थक होगा जब रोजगार के नए अवसर पैदा करें

मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि, यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज यहां दो महत्वपूर्ण यात्राओं का शुभारंभ हो रहा है, एक हमारी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर नवाचारकर्ताओं के माध्यम से सपनों को उद्यम में बदलने प्रात्साहित करेगी।

महिला स्वावलंबी बनती है तब परिवार मजबूत होता है

छत्तीसगढ की कृषि परंपरा में मिलेट अर्थात मोटे अनाज का विशेष महत्व रहा है। आज वहीं पारंपरिक 'श्री अन्न' (मिलेट) पोषण के साथ-साथ अब आय का नया जरिया बन रहा है। मिलेट पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ किसानों, ग्रामीण परिवारों और महिला उद्यमियों के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को निःशुल्क मिलेट हेल्थ कार्ट प्रदान किए जाने के साथ ही उन्हें एक सक्षम व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने के लिए उत्पाद निर्माण, एफएसएसएआई मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवसाय प्रबंधन और विपणन का संपूर्ण प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने महिला स्व-सहायता-समूहों को आत्मनिर्भरता से जोड़ने की इस पहल पर बल देते हुए बताया कि जब एक महिला स्वावलंबी बनती है तो उसका परिवार मजबूत होता है और पूरे समुदाय में आत्मविश्वास पैदा होता है।

महिला स्व-सहायता समूह ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी

राज्यपाल श्री डेका ने युवा नवाचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, 24 नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को कुल 50 लाख की इग्निशन ग्रांट प्रदान की जा रही है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार के मार्ग में असफलताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे सीखकर निरंतर आगे बढ़ना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है।

सहकारिता से समृद्धि की ओर बढ़ेगा समाज : कनीराम शर्मा

आईआईटी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन समारोह कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहकारिता के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। सामान्य व्यक्ति की आय में यदि वृद्धि करनी है, सामाजिक-आर्थिक संतुलन यदि ठीक बनाकर रखना है, तो आर्थिक समन्वय के लिए सहकारिता के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा सफल मॉडल नहीं है। कई बार आर्थिक संवर्धन के लिए शासकीय अनुदान तो मिलता है, लोग काम भी करते हैं, लेकिन एक समय-सीमा पूर्ण होने के बाद जब शासकीय अनुदान खत्म हो गया तो योजना भी समाप्त हो जाती है। ऐसा देखने में आता है।

सरकारी सहायता का समुचित उपयोग करें

सहकारिता का मॉडल ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई शासकीय सहायता मिली है, तो उसका समुचित उपयोग करें और यदि को-ऑपरेटिव मॉडल को ठीक से विकसित किया तो यह जीवनभर और लंबे समय के लिए आजीविका का ऐसा साधन सुदृढ़ करता है। सहकार भारती देशभर में ऐसे समस्त कार्यों को गति देती है। सामान्य व्यक्ति की समृद्धि हो, जैसा भारत सरकार का नारा है—सहकार से समृद्धि। प्रधानमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सहकारिता मॉडल को देखते हुए स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया गया। इसके संबंध में सहकार भारती द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए थे और वर्तमान सरकार ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 06 जुलाई 2021 को स्वतंत्र रूप से सहकारिता मंत्रालय का गठन कर दिया।

जिला स्तर पर सहकारी संस्थाओं को एकजुट करना जरूरी : सौरभ शर्मा

- **धनोरा में सहकारी गतिविधियों की जानकारी, जिला सहकारी संघ गठन के लिए दिया गया मार्गदर्शन**

कोंडागांव। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित धनोरा, विकासखंड केशकाल, जिला कोंडागांव में सहकारिता से जुड़े प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों, उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सहकारी आंदोलन को ग्राम स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि, सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर पर सहकारी संस्थाओं को एकजुट कर उन्हें एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ के गठन की पहल की जा रही है। उन्होंने जिला सहकारी संघ के गठन की प्रक्रिया, उसके उद्देश्यों एवं कार्यों के संबंध में उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन दिया।

सहकारी आंदोलन को मजबूती देने की

अपील : श्री शर्मा ने कहा कि, जिला सहकारी संघ के माध्यम से जिले की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं क्षमता विकास की गतिविधियों को गति मिलेगी। उन्होंने सहकारी प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से सक्रिय सहभागिता के साथ जिले में सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा, मानसेवी सदस्य श्री कनीराम शर्मा एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित धनोरा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया कीर्तिमान

लगातार दो पेराई सत्रों के लिए मिला नेशनल को ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन का सर्वोच्च शुगर रिकवरी एफिशिएंसी अवार्ड

कवर्धा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। कारखाने को पेराई सत्र 2024-25 एवं 2025-26, दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च शुगर रिकवरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ÷हाइएस्ट शुगर रिकवरी एफिशिएंसी अवार्ड÷ के लिए चयनित किया गया है।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। लगातार दो पेराई सत्रों के लिए यह सम्मान प्राप्त होना कारखाने की तकनीकी दक्षता, बेहतर संचालन व्यवस्था और उत्कृष्ट शुगर रिकवरी का प्रमाण है। इस उपलब्धि से कारखाने के साथ-साथ जिले और प्रदेश को भी राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली है।

दोनों पेराई सत्रों के पुरस्कार 22 सितम्बर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल,

विभिन्न राज्यों के मंत्री, निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी तथा देशभर की सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है।

नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन देश की लगभग 260 सहकारी चीनी मिलों और नौ राज्यस्तरीय चीनी महासंघों का प्रतिनिधित्व करता है। फेडरेशन द्वारा प्रतिवर्ष गन्ना विकास, तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, शुगर रिकवरी, डिस्टिलरी संचालन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मिल के समग्र प्रदर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी चीनी मिलों को सम्मानित किया जाता है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा लगातार दो वर्षों तक सर्वोच्च शुगर रिकवरी की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफलता में क्षेत्र के अंशधारी कृषकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण गन्ने की आपूर्ति तथा कारखाने के कर्मचारियों की मेहनत, तकनीकी दक्षता और समर्पित कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कारखाने की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों, समस्त अंशधारी कृषकों एवं कर्मचारियों में हर्ष का वातावरण है।

सहकार नवाचार को बढ़ावा दे रहा एनसीडीसी सहकारी समितियों को 25 लाख तक अनुदान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारी क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकार नवाचार योजना (स्ङ्क्ष्स्) के माध्यम से नई पहल की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभ इस योजना के तहत पात्र प्राथमिक सहकारी समितियों को नवीन एवं व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक पूर्ण अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों को नई तकनीक अपनाने, नवीन उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करने, नए व्यावसायिक मॉडल तैयार करने, बाजार से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने तथा टिकाऊ एवं स्थायी समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवश्यकता के अनुसार एनसीडीसी द्वारा अनुदान के साथ ऋण सहायता का प्रावधान भी किया गया है।

सहकार नवाचार योजना का लाभ कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण तथा ग्रामीण सेवाओं से जुड़ी सहकारी समितियों को मिल सकता है। डिजिटल तकनीक, मूल्य संवर्धन, आधुनिक उत्पादन प्रणाली, नवीन सेवाओं तथा टिकाऊ व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं को इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

एनसीडीसी का मानना है कि जमीनी स्तर की सहकारी समितियों के पास नवाचार एवं विकास की क्षमता है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अनेक विचार व्यवहारिक रूप नहीं ले पाते। अनुदान सहायता के माध्यम से ऐसी वित्तीय बाधाओं को कम करने तथा सहकारी समितियों को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह पहल एनसीडीसी की सहकारी क्षेत्र में उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 'सहकार नवाचार योजना' के माध्यम से सहकारी समितियों के नवोन्मेषी विचारों को व्यवहार्य एवं टिकाऊ उद्यमों में परिवर्तित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू, मोबाइल एप से दर्ज होगी खेत और फसल की जानकारी

मुंगेली। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से गिरदावरी में दर्ज फसल एवं रकबे की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मैदानी सत्यापन और रैंडम सत्यापन का कार्य लगातार जारी है।

अब किसानों के खेतों का डेटा सीधे सैटेलाइट और मोबाइल ऐप से ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। अभियान के तहत इस बार खरीफ सीजन की फसलों का सही रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इस डिजिटल सर्वे में लगे सर्वेयर खेतों में जाकर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि डीएससी के तहत फसल क्षेत्र और उत्पादन का सटीक आकलन करना कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाना तथा किसानों तक लक्षण सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी एवं मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज ने विकासखंड मुंगेली के ग्राम धरमपुरा सहित अन्य ग्रामों में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर सर्वे की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में शत-प्रतिशत एवं त्रुटिरहित, ई-गिरदावरी कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जिले में विभिन्न अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बनी शंभू बारी के परिवार का सहारा

■ **प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से जरूरत के समय मिल रहा संबल**

रायपुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े परिवारों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व का आधार बन रही हैं। योजनाओं का प्रभाव तब और अधिक सार्थक दिखाई देता है, जब एक परिवार को आजीविका के साथ आवास और सामाजिक सुरक्षा का लाभ एक साथ मिलता है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पतरापारा निवासी शंभू बारी का परिवार इसका उदाहरण है।

भूमिहीन कृषि मजदूर शंभू बारी को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। सीमित आय और अनिश्चित रोजगार के बीच मिलने वाली यह सहायता परिवार के लिए जरूरत के समय महत्वपूर्ण सहारा बनी है। शंभू बारी बताते हैं कि इस राशि

का उपयोग वे घरेलू जरूरतों, बीमारी के समय उपचार और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में करते हैं।

भूमिहीन परिवार को मिला पक्के आवास का सहारा

शंभू बारी का परिवार लंबे समय तक स्वयं के पक्के मकान के अभाव में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करता रहा। शासन की पहल से उन्हें भूमि उपलब्ध कराई गई और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का आवास भी मिला। अब उनका परिवार अपने सुरक्षित और पक्के घर में रह रहा है। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि वर्षों से देखे जा रहे सुरक्षित आशियाने के सपने का साकार रूप है।

कई योजनाओं का लाभ बना मजबूत जीवन का आधार

शंभू बारी कहते हैं कि अलग-अलग योजनाओं से मिले लाभ ने उनके परिवार की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव लाया है। भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में मिलने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का घर और पत्नी को मिल रही महतारी वंदन योजना की राशि ने परिवार को आर्थिक सहारा देने के साथ भविष्य के प्रति भरोसा भी बढ़ाया है। शंभू बारी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से हमें साल में 10 हजार रुपये मिलते हैं। यह राशि हमारे जरूरी कामों में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें पक्का घर मिला है और मेरी पत्नी को महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं। इन योजनाओं से हमारे परिवार को बहुत सहारा मिला है।

महतारी वंदन योजना से परिवार की महिलाओं को आर्थिक संबल

परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महतारी वंदन योजना भी सहायक बन रही है। शंभू बारी की पत्नी को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो रही है। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि घरेलू जरूरतों और छोटे-छोटे खर्चों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है।

साल भर बाद पहली बार, सबके सामने खुला हिसाब-किताब

विशेष श्रृंखला भाग-3 : पहली आमसभा — सवाल पूछने का हक़

पुरूषोत्तम सोनी, प्रभारी व्याख्याता
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर

पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि कैसे एक गाँव में प्रबंध समिति का गठन सामूहिक नेतृत्व की नींव बना। साल भर बीतते-बीतते उसी गाँव में एक सूचना पत्र दीवार पर चस्पा हुआ – 'वार्षिक साधारण सभा, आगामी रविवार, पंचायत भवन में।' यह सूचना जितनी साधारण दिखी, उतनी ही महत्वपूर्ण थी – क्योंकि यहीं पहली बार हर सदस्य को अपनी संस्था का पूरा हिसाब-किताब देखने और सवाल पूछने का मौका मिलने वाला था।

साल भर की मेहनत, एक दिन का हिसाब

रविवार सुबह पंचायत भवन धीरे-धीरे भरने लगा। कुछ सदस्य पहली बार किसी संस्था की सभा में आए थे, कुछ के मन में उत्सुकता थी, कुछ के मन में हल्का संकोच भी। कोषाध्यक्ष ने एक बड़े तख्ते पर साल भर की आमदनी और खर्च का ब्योरा टांग दिया। यह दृश्य ही आमसभा की सबसे बड़ी खूबी बयान करता है – यहाँ कुछ भी बंद कमरे में नहीं होता, सब कुछ सबके सामने रखा जाता है। वार्षिक साधारण सभा सहकारी समिति की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यही वह अवसर है जब हर सदस्य – चाहे वह प्रबंध समिति में हो या न हो – संस्था के कामकाज पर सीधे अपनी राय रख सकता है।

सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं, अधिकार है

सभा शुरू होते ही एक सदस्य ने खड़े होकर पूछा – 'खाद खरीद में जो पैसा खर्च हुआ, उसका हिसाब थोड़ा और विस्तार से समझा दीजिए।' कुछ लोगों को यह सवाल असहज करने वाला लगा, पर अध्यक्ष मुस्कुराए और पूरा ब्योरा समझाया। बाद में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा – सवाल पूछना अविश्वास की निशानी नहीं, बल्कि जागरूक सदस्यता की पहचान है। जितने सवाल उतनी ही मज़बूत संस्था।

— **समिति अध्यक्ष**

यही वह भावना है जो आमसभा को सार्थक बनाती है। जहाँ सदस्य चुप बैठे रहते हैं, वहाँ संस्था धीरे-धीरे कुछ लोगों के इर्द-गिर्द सिमटने लगती है। जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पारदर्शिता अपने आप बनी रहती है।

दो गाँवों की सभा, दो अलग कहानियाँ

पड़ोस के गाँव में उसी दिन एक और समिति की सभा हुई, पर वहाँ माहौल कुछ अलग था। सूचना पत्र देर से भेजा गया, हिसाब-किताब जल्दी-जल्दी में पढ़ा गया, और सवालों के लिए समय ही नहीं बचा। सभा बमुश्किल आधे घंटे में खत्म हो गई।

साल भर बाद जब दोनों समितियों की स्थिति की तुलना हुई, तो फ़र्क साफ था – जहाँ सभा में खुलकर चर्चा हुई थी, वहाँ सदस्यों का भरोसा बढ़ा; जहाँ सभा औपचारिकता बनकर रह गई, वहाँ सदस्य धीरे-धीरे दूरी बनाने लगे।

आमसभा जितनी खुली होगी, संस्था पर भरोसा उतना ही गहरा होगा।

हर सदस्य की आवाज़ की कीमत

आमसभा में हर सदस्य का मत बराबर मूल्य रखता है – चाहे वह संस्था में सबसे पुराना सदस्य हो या सबसे नया। आगामी वर्ष की कार्ययोजना, महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव और प्रबंध समिति के कामकाज पर मुहर, यह सब निर्णय सभा की सामूहिक सहमति से ही लिए जाते हैं। जिस गाँव की कहानी से हमने शुरुआत की, वहाँ सभा के अंत में एक बुजुर्ग सदस्य ने कहा – 'आज पहली बार लगा कि यह संस्था सच में हमारी अपनी है।' यही वाक्य आमसभा के असली उद्देश्य को सबसे सरल शब्दों में बयान कर देता है।

नई समितियों के लिए सीख

जो समितियाँ समय पर सूचना भेजती हैं, हिसाब-किताब खुलकर सामने रखती हैं और सवालों के लिए पर्याप्त समय देती हैं, वे सदस्यों का भरोसा लंबे समय तक बनाए रख पाती हैं। आमसभा कोई औपचारिक रस्म नहीं, बल्कि सहकारिता की आत्मा है।

अगले अंक में हम पढ़ेंगे — अंशपूँजी और आर्थिक अनुशासन की कहानी, जहाँ हर सदस्य की छोटी-छोटी हिस्सेदारी मिलकर संस्था की बड़ी ताकत बनती है। तब तक के लिए, सहकार समाचार पढ़ते रहिए।

मछली पालन के सपने को मिला शासकीय अनुदान का सहारा

- **दुर्गावती ने शुरू की आत्मनिर्भरता की नई यात्रा**
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 60 प्रतिशत अनुदान, बायोफ्लॉक तालाब से 5 से 6 क्विंटल उत्पादन और करीब एक लाख रुपये आय**

रायपुर। कभी पूंजी के अभाव में अधूरा रह गया सपना, अब आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद बन चुका है। बलरामपुर जिला के ग्राम करीचलगली की श्रीमती दुर्गावती सिरोटिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने मछली पालन के सपने को हकीकत में बदल दिया है। शासकीय अनुदान और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन से तैयार उनका बायोफ्लॉक तालाब अब उनके लिए स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती का नया आधार बन रहा है।

श्रीमती दुर्गावती की मछली पालन में लंबे समय से रुचि थी। वे चाहती थीं कि अपना व्यवसाय शुरू कर परिवार की आय बढ़ाएं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी बीच उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना ने उनके सपने को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

योजना के तहत उन्होंने वर्ष 2025-26 में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण कराया। इसके लिए मत्स्य विभाग के माध्यम से उन्हें परियोजना लागत का 60 प्रतिशत शासकीय अनुदान मिला, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि उन्होंने स्वयं वहन की। विभाग ने उन्हें आवश्यक तकनीकी सहयोग और मछली पालन से संबंधित मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया।

बायोफ्लॉक तालाब से बढ़ेगी आय की संभावनाएं

तालाब तैयार होने के बाद दुर्गावती अब मछली पालन को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। बायोफ्लॉक तालाब से उन्हें लगभग 5 से 6 क्विंटल मछली उत्पादन की संभावना है। इससे करीब एक लाख रुपये तक की आय होने की उम्मीद है। उत्पादन और अनुभव बढ़ने के साथ वे भविष्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने की भी योजना बना रही हैं। श्रीमती दुर्गावती बताती हैं कि आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण जिस काम को शुरू करने का सपना वर्षों से मन में था, उसे शासकीय योजना ने पूरा करने का अवसर दिया। उनके लिए यह सहायता केवल अनुदान नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का जरिया बनी है।

अनुदान से मिला अवसर, अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम

श्रीमती दुर्गावती का कहना है कि जब शासन की योजना, आर्थिक सहयोग और विभागीय मार्गदर्शन एक साथ मिलता है, तो सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वरोजगार की मजबूत नींव रखी जा सकती है। उनका बायोफ्लॉक तालाब इसी विश्वास का उदाहरण है। करीचलगली में तैयार यह तालाब अब श्रीमती दुर्गावती के लिए सिर्फ मछली उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक मजबूती, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भविष्य की नई शुरुआत है। उनकी पहल यह संदेश देती है कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर ग्रामीण महिलाएं अपनी रुचि और हुनर को व्यवसाय में बदल सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

हरियाली के साथ ग्रामीणों को रोजगार की नई राह दे रहा विकसित भारत- जीरामजी

- **बावनपुरी में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 पौधों का मिश्रित वृक्षारोपण, 2,667 मानव दिवस रोजगार का सृजन**

13 प्रजातियों के पौधों से संवरेगा स्थानीय पर्यावरण

मिश्रित वृक्षारोपण के अंतर्गत 13 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। आने वाले वर्षों में इनके वृक्ष का रूप लेने से क्षेत्र में हरियाली का विस्तार होगा। साथ ही वृक्षारोपण मिट्टी एवं जल संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में भी सहायक होगा। पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में ग्राम बावनपुरी की संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी जनभागीदारी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से लगाए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

रायपुर। विकसित भारत - जीरामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह ग्रामीण परिवारों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है, जो भविष्य में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी सोच का प्रभाव कोण्डागांव जिले के जनपद पंचायत बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरापारा के आश्रित ग्राम बावनपुरी में देखने को मिल रहा है। यहां समुदाय के लिए पंक्तिबद्ध मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 पौधों का रोपण किया गया है। इस कार्य के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

11 लाख रुपए की लागत से 2,667 मानव दिवस रोजगारः बावनपुरी में संचालित वृक्षारोपण परियोजना के तहत लगभग 11 लाख रुपए की लागत से 2,667 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। ग्रामीण श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर आय का साधन मिला है और रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिल रही है। यह कार्य इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ जोड़कर एक साथ रोजगार, पर्यावरण और आजीविका को मजबूती दी जा सकती है।

चिउरगांव में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण आयोजित

- **सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम चिउरगांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक श्री मितेश पानीग्राही ने समूह की महिलाओं को सहकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, उद्भव एवं विकास के साथ-साथ सहकारी समिति की सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, बैठकों की प्रक्रिया, समिति का पंजीयन एवं बैंक लिंकिंग के संबंध में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षक श्री पानीग्राही ने महिलाओं को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यवसाय विकास एवं स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराया। विशेष रूप से मछली पालन, बकरी पालन एवं गौ पालन जैसे आयवर्धक गतिविधियों को समूह के माध्यम से अपनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर सहकारिता के माध्यम से उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर परिवार एवं गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने तथा सामूहिक रूप से व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रशिक्षण में 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन सकती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता करते हुए सहकारिता एवं सामूहिक व्यवसाय से संबंधित विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं रखीं। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं में सहकारी भावना, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता तथा स्वरोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की पहल सहकारी बैंकों में 1,360 पदों पर होगी भर्ती

■ रायपुर में सर्वाधिक 508 और बिलासपुर क्षेत्र में 444 पदों पर होगी भर्ती

पांच सहकारी बैंक क्षेत्रों में 198 बैंक कर्मचारियों और 1,162 समिति प्रबंधकों की भर्ती को मिली अनुमति

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।

स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं। समिति प्रबंधक के पदों में 596 पद सीधी भर्ती तथा 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बैंकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। इन निर्देशों के बाद विभाग ने प्रस्तावों का परीक्षण कर भर्ती की अनुमति जारी कर दी है।

युवाओं को मिलेगा अवसर, सहकारी व्यवस्था होगी मजबूत : सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सहकारी व्यवस्था को अधिक सक्षम और किसान हितैषी बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों

पर भर्ती की अनुमति इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, ÷इस भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति होने से किसानों एवं खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सरलता और समयबद्धता के साथ मिल सकेंगी।

पारदर्शी तरीके से भर्ती के निर्देश: केदार कश्यप ने कहा कि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों का संचालन बेहतर होगा तथा कम्प्यूटरीकरण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

पांच क्षेत्रों में होगी भर्ती

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर क्षेत्र में सर्वाधिक 508 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर क्षेत्र में 444 पद, बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र में 187 पद, दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र में 154 पद और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी क्षेत्रों के बैंक और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाएंगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

बैंक संवर्ग के स्वीकृत पदों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक के पद शामिल हैं। इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होने से बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

निर्धारित नियमों के अनुसार होगी चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पद संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बैंकों को भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों का पालन करना होगा। इसके साथ ही बैंकों की वित्तीय स्थिति और निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

किसानों और खाताधारकों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं

नए कर्मचारियों की नियुक्ति से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को गति मिलेगी। किसानों एवं खाताधारकों से संबंधित बैंकिंग कार्य, ऋण प्रकरण, लेन-देन और अन्य सेवाओं का संचालन अधिक सुगमता एवं समयबद्धता के साथ किया जा सकेगा। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के दैनिक कार्यों के संचालन, अभिलेखों के संधारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी नए कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में हलषष्ठी पर भगवान बलराम की पूजा अर्चना

दुर्ग। भगवान बलराम की जयंती एवं हलषष्ठी व्रत के शुभ अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के प्रधान कार्यालय परिसर में किसानों के आराध्य देवता भगवान बलराम की प्रतिमा की विधि-विधान से की गई। प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग की उपस्थिति में पूजा अर्चना किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित सहकारी जन प्रतिनिधियों द्वारा किसानों, श्रमिकों और अन्नदाताओं की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की साथ ही देश और प्रदेश में किसानों की मेहनत सफल हो तथा कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि होने की कामना की। इस अवसर पर श्री एस.के.वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारिता के जनप्रतिनिधि श्री रमाकांत द्विवेदी, श्री लेखूदास, श्री राजेन्द्र यादव, श्री

अजय तिवारी, श्री योगेन्द्र धर दिल्लीवार, बैंक अधिकारी श्री हृदेश शर्मा, सुश्री कुसुम ठाकुर, श्री के.के.नायक, श्री रोहित वर्मा, श्री धीरेन्द्र देवांगन, श्री एस.पी.वाहने, सहित बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखा दुर्ग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

एग्रीस्टेक पंजीयन बिना नहीं बिकेगा धान, कलेक्टर ने की समीक्षा

दुर्ग। धान खरीदी के लिए किसानों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार 1 सितंबर को कलेक्टर श्री अभीजीत सिंह की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एग्रीस्टेक एवं बकेट क्लेम में किसानों के पंजीयन के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारियों, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध सेवा सहकारी समितियों के समिति प्रबंधक / प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई।

सह खातेदारों का भी पंजीयन आवश्यक : कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि, बिना एग्रीटेक पंजीयन धान नहीं बिकेगा, सह खातेदारों का भी पंजीयन होना भी आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस वर्ष 2026-27 में धान बिकी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं सह-खातेदारों का बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) अनिवार्य रहेगा। बकेट क्लेम तब बनता है जब किसी कृषि भूमि में एक से अधिक हिस्सेदारी होती है। प्रत्येक हिस्सेदार के नाम से बकेट आईडी बनती है, जिसे एग्रीटेक में पंजीयन कराना आवश्यक है।

संस्थागत छूट को भी किया गया समाप्त : कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि, बकेट क्लेम और किसानों के पंजीयन का कार्य समय-सीमा में पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर सह खातेदारों का सत्यापन, सहमति और पंजीयन प्रक्रिया को पूरा किया जावेगा। इस वर्ष संस्थागत छूट को भी समाप्त कर दिया गया है, इस संबंध में भी दुर्ग कलेक्टर ने बताया है कि पिछले वर्षो में संस्थागत पंजीयन वाले किसानों को जो विशेष छूट दी गई थी, उसे इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है।

जिला सहकारी संघ धमतरी की आठवीं वार्षिक आमसभा संपन्न

धमतरी। जिला सहकारी संघ धमतरी की आठवीं वार्षिक आम सभा 3 सितंबर गुरुवार को वन विभाग के नवीन प्रशिक्षण हाल डिपो परिसर धमतरी में संपन्न हुई। उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर, सहायक उपायुक्त सहकारिता सुश्री सुमन ध्रुव, जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू, अधिकारी कर्मचारी सहकारी संघ के जिला अध्यक्ष नेमीचंद देव की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन, छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पूजा अर्चन पश्चात राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान व राज्य गीत उपरांत अतिथियों के स्वागत से प्रारंभ हुआ।

पढ़ा गया वार्षिक प्रतिवेदन

कार्यक्रम में संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का पठन किया गया, पश्चात संघ प्रबंधक द्वारा सूचना अनुसार विषयसूची के अनुरुप पिछली आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव व निर्णय की पुष्टि व अनुमोदन, वर्ष 24-25 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रको का अनुमोदन, वर्ष 24-25 के अंकेक्षण आक्षेप का निराकरण से अवगत व अनुमोदन, वर्ष 25-26 के अअंकेक्षित वित्तीय पत्रको का अनुमोदन, वर्ष 26-27

के अनुमानित (बजट) का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत संघ के वर्ष 26-27 के लेखाओं की संपरीक्षा पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल के संपरीक्षकों से कराए जाने बाबत, वर्ष 25-26 में हुए प्रचार प्रसार कार्यक्रम तथा वर्ष 26-27 में संभावित प्रचार प्रसार कार्यक्रम का अनुमोदन पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिस पर उपस्थित सभी संघ प्रतिनिधि सदस्यों ने विचार विमर्श व प्रश्नोत्तर पश्चात सर्वसम्मति से सहमति व स्वीकृति प्रदान की गई।

पैक्स समितियों की जमा अभिदाय राशि पर चर्चा

विषय सूची के प्रस्ताव क्रमांक 9 पर जिसमें पैक्स समितियों द्वारा जमा गत 3 वर्षो का अभिदाय राशि कोऑपरेटिव बैंक रायपुर द्वारा संघ को अब तक भुगतान न करने पर उपस्थित पैक्स प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से इस पर बैंक अध्यक्ष को लिखित जानकारी देने तथा प्रधान कार्यालय द्वारा इस पर शीघ्र कार्रवाई न करने पर सभी प्राधिकृत अधिकारी एक टीम बनाकर रायपुर बैंक कार्यालय से संपर्क किए जाने का निर्णय लिया गया।

इन्होंने भी रखे विचार

कार्यक्रम में पैक्स तरसीवा के प्राधिकृत अधिकारी केशवराम साहू, पैक्स बोडरा के प्राधिकृत अधिकारी चिरौंजी लाल साहू, छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी महासंघ के नरेंद्र साहू ने अपने विचार व्यक्त किये। नेमीचंद देव ने जिला सहकारी संघ के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर ने कहा कि, जिला सहकारी संघ योजनाबद्ध तरीके से अपने उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण का कार्य पूरे जिले में सफलतापूर्वक आयोजित कर रही है जिसके लिए संघ बधाई का पात्र है। इस अवसर पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एस प्रसाद, सहकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा, गुणेश वैष्णव, अवधेश चंद्राकर, संगीता सिन्हा, तोषी भूआर्य सहित जिले के बड़ी संख्या में पैक्स प्राधिकृत अधिकारीगण व अन्य समितियों से जुड़े सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता ने किया।

देवभोग उरला डेयरी प्लांट में हुई दुग्ध उत्पादक किसान संगोष्ठी

- **कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया नवीन कैंटीन का उद्घाटन, पशुपालकों के लिए पुस्तिकाओं, देवभोग रेडियो जिंगल, ऑडियो रिंगटोन एवं गीत का विमोचन**

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (CCDF) के देवभोग उरला डेयरी प्लांट में आज दुग्ध उत्पादक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय कृषि मंत्री द्वारा देवभोग उरला डेयरी प्लांट परिसर में नवीन कैंटीन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई पुस्तिकाओं उत्तम पशुपालन पद्धतियों के लिए बुनियादी मार्गदर्शिका एवं मवेशियों के प्रमुख रोगों के लिए पारंपरिक उपचार विधियाँ÷ का विमोचन किया गया। संगोष्ठी के दौरान देवभोग के रेडियो जिंगल/ऑडियो, रिंगटोन एवं गीत का भी विमोचन माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया।

दूध उत्पादकों से मंत्री ने किया संवाद

कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादक किसान, महिला दुग्ध उत्पादक किसान, दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी ने किसानों एवं महिला दुग्ध उत्पादकों को मंच पर आमंत्रित कर उनसे संवाद किया और उनके द्वारा किए जा रहे दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन कार्यों की जानकारी ली। मंत्री जी ने किसानों से NDDB एवं CCDF द्वारा प्रदेश में किए जा रहे डेयरी विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की तथा भविष्य में छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयासों पर जानकारी ली। इस अवसर पर CCDF के प्रबंध संचालक द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी को NDDB एवं CCDF के सहयोग से प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न कार्यों तथा देवभोग ब्रांड के विकास एवं विस्तार की जानकारी दी गई।

पहचान बनाने के लिए हो समन्वित प्रयास

मंत्री जी ने कहा कि, देवभोग के दूध एवं दुग्ध उत्पादों की पहचान केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित न रहकर पूरे देश में बने, इसके लिए किसानों, दुग्ध सहकारी समितियों, CCDF एवं NDDB के समन्वित प्रयासों को और मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों एवं महिला पशुपालकों की भूमिका की सराहना करते हुए डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के संचालक श्री वर्मा , वरिष्ठ अधिकारी, दुग्ध उत्पादक किसान, महिला किसान एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे में सारंगढ़-बिलाईगढ़ प्रदेश में अव्वल, 87 प्रतिशत कार्य के साथ प्रथम स्थान

- **सरसींवा और भटगांव में 93 प्रतिशत से अधिक सर्वे पूर्ण, जिले में अब तक 47 हजार 350 प्लॉटों का सर्वे**

रायपुर। डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के प्रभावी और बेहतर क्रियान्वयन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश स्तरीय रिपोर्ट में जिले ने 87 प्रतिशत कार्य के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वाधिक कार्य करने वाले प्रदेश के शीर्ष तीन जिलों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहले स्थान पर है, जबकि खैरागढ़ 86 प्रतिशत के साथ दूसरे और कोरिया 81 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।

जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य को प्रशासन द्वारा लगातार प्राथमिकता देते हुए मैदानी स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। 6 सितंबर 2026 को शाम 4.30 बजे तक की तहसीलवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 53 हजार 524 प्लॉटों के विरुद्ध 47 हजार 350 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है, जो 88.45 प्रतिशत है। जिले में 35 हजार 476 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं और अनुमोदन की प्रगति 74.93 प्रतिशत दर्ज की गई है।

तहसीलवार प्रगति भी उत्साहजनक

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सभी छह तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। सारसींवा तहसील ने सर्वे कार्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 हजार 187 प्लॉटों में से 7 हजार 653 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण कर 93.27 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। यहां 5 हजार 348 सर्वे अनुमोदित किए गए हैं। इसी प्रकार भटगांव तहसील में कुल 6 हजार 235 प्लॉटों के विरुद्ध 5 हजार 847 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया गया है, जो 93.15 प्रतिशत है। तहसील में 3 हजार 748 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं। जिले की सबसे बड़ी तहसीलों में शामिल सारंगढ़ तहसील में कुल 16 हजार 134 प्लॉटों के विरुद्ध 14 हजार 32 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण कर 88.60 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।

शत-प्रतिशत लक्ष्य तक जारी रहेगी तेजी

जिले की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने तक इसी गति और गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए लंबित प्लॉटों के सर्वे कार्य में तेजी लाने तथा प्रदेश में जिले की अग्रणी स्थिति को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को मैदानी अमले के साथ सतत समन्वय स्थापित कर शेष सर्वे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान की उपलब्धि को निरंतर बनाए रखना है।

जल जीवन मिशन से संवर रही नारायणपुर के वनांचल की तस्वीर

- **घर-घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली**
- **379 गाँवों के 22,923 परिवारों तक पहुँचा नल कनेक्शन**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूर, वनांचल और दुर्गम इलाकों में बसे नारायणपुर जिले में जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की नई भोर लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जिले के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब धरातल पर रंग ला रहा है। हर घर जल की इस मुहिम ने न केवल पेयजल का संकट दूर किया है, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन को आसान बनाकर उनके जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाया है।

22 हजार 923 परिवारों को मिला नल कनेक्शन

जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के 379 गाँवों में निर्धारित 33,009 घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 22,923 परिवारों को सफलतापूर्वक नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बनी बड़ा सहारा

भौगोलिक रूप से कठिन और दूरस्थ अंचलों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोलर पंपों को मजबूत आधार बनाया गया है। स्वीकृत सोलर पंप 1,084, स्थापित सोलर पंप 852, वर्तमान में चालू सोलर पंप 750, सौर ऊर्जा से 20 हजार 138 लाभान्वित घरों को सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

119 गाँव में हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली

इन प्रयासों का परिणाम है कि जिले के 119 गाँवों के 7,276 परिवारों को पूरी तरह शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। इन गाँवों को 'हर घर जल' गाँव के रूप में प्रमाणित कर इनका प्रबंधन सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 3,572 हैंडपंप भी ग्रामीणों की दैनिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं को राहत

जल आपूर्ति के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता, पाइपलाइन के रख-रखाव और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शुद्ध पेयजल की सुलभ उपलब्धता से मौसमी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं, पानी लाने में लगने वाले समय की बचत होने से विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे नारायणपुर के दुर्गम अंचलों में विकास और खुशहाली की नई राह खुल रही है।

सहकारी बैंक दुर्ग के ऋण उप समिति की बैठक

दुर्ग। अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग प्रीतपाल बेलचंदन की अध्यक्षता में संचालक मण्डल एवं ऋण उप समिति की बैठक 3 सितम्बर को सम्पन्न हुई। बैठक में श्री नरेश यदु उपाध्यक्ष, श्री सुमन कुमार कोरम सहायक संचालक कृषि, श्री सतीश पाटले उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग एवं श्री एस.के.वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

बैंक के कार्यक्षेत्र जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा के अंतर्गत 11 सहकारी समितियों से संबंधित कृषकों का फसल ऋणों हेतु पूरक साख सीमा 2026-27 से 2028-29 हेतु 811 किसानों को 9.56 करोड़ रु., गन्ना उत्पादन हेतु 6 कृषक को साख सीमा 5.62 लाख रु., उद्यानिकी फसल केला हेतु 3 किसानों को 7.73 लाख रु., का ऋण स्वीकृत किया गया है।

95 किसानों को गौपालन के लिए 1.96 बोटे गए गौपालन हेतु 95 किसानों को 1.96 करोड़ एवं नवीनीकरण अंतर्गत 38 किसानों को 63.30 लाख, मत्स्य पालन अंतर्गत 2 किसानों को 2.62 लाख, बकरीपालन हेतु 2 कृषकों को 4.32 लाख, कुक्कुट पालन हेतु 3 किसानों को 6.40 लाख, मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण अंतर्गत 8 किसान को 45.64 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत 2 किसान को 9 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह के हितग्राहियों के मांग अनुसार 3 समूह को 12.60 लाख ऋण स्वीकृत किया गया। बैंक के माध्यम से ऋण नीति अनुसार उप संचालक कृषि/ उद्यानिकी/ पशुपालन/मत्स्य विभाग के विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कृषकों के मध्य करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ताकि बैंक के माध्यम से इन योजनाओं में अधिकाधिक कृषक लाभान्वित हो। बैठक में सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक, श्री एस.पी.वाहने शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

धान खरीदी, चावल भंडारण, किसान पंजीयन और गोदाम निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

- खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सचिव खाद्य श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक खाद्य डॉ. फरिया आलम, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री विलास भोसकर संदीपन, प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री जितेन्द्र शुक्ला, महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम श्री दीपक शर्मा आदि अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मंत्री श्री बघेल ने बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की गति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। माह सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के 2 माह के चावल का समयानुसार भंडारण एवं वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन की तैयारियों यथा - बारदानों की व्यवस्था, नवीन खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश दिये गये।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक में जिला खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, प्रबंधक राज्य भण्डार गृह निगम एवं नापतौल के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

शॉर्टेज की मात्रा में कमी लाये के निर्देश

खरीफविपणन वर्ष 2026-27 में किसान पंजीयन के संबंध में शेष किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये गये। खरीदी केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में शॉर्टेज की मात्रा में कमी लाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये। राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम निर्माण प्रगति की समीक्षा की गई एवं निर्माणाधीन गोदामों के समयानुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। नापतौल की समीक्षा करते हुए धरमकांटा का सत्यापन धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में मंत्री ने सिटी गैस वितरण योजना के संबंध में विभागीय वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।

पोंदुम-पातरपारा के किसानों को मिला सहकारिता और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण

- नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर की जानकारी से बढ़ा किसानों का उत्साह
- दुग्ध सहकारी समिति से बढ़ेगी आय, पशुपालन से जैविक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

बीजापुर। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के दूरस्थ ग्राम पोंदुम-पातरपारा में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में किसानों को जहां सहकारिता की शक्ति और सामूहिक विकास का संदेश मिला, वहीं आधुनिक कृषि में उपयोगी नैनो उर्वरकों की जानकारी ने ग्रामीण कृषकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया।

सहकारिता से आय वृद्धि की नई संभावनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में 'आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना' अंतर्गत बस्तर जिला सहकारी संघ, जगदलपुर एवं इफको क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर के सहयोग से बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंदुम-पातरपारा में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन पातरपारा के समक्ष नवनिर्मित शेड में आयोजित किया गया।

सहकारिता के काम करने का तरीका समझाया गया

कार्यक्रम में ग्राम सरपंच श्री पोदिया राम अका एवं श्री दशमन माझी, प्राधिकृत लैम्पस भैरमगढ़ की गरिमामय उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने उपस्थित कृषक सदस्यों को सहकारिता के अर्थ, महत्व एवं सिद्धांतों की जानकारी देते हुए लैम्पस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और गोपालन की संभावनाओं को देखते हुए 'दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति' के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि, दुग्ध सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण किसानों को नियमित आय का एक अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकता है। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा मिलने से जैविक खेती के लिए आवश्यक गोबर की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

नैनो उर्वरकों की जानकारी से उत्साहित हुए किसान

प्रशिक्षण कार्यक्रम में इफको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री लाल बहादुर सिंह, कृषि स्नातक प्रशिक्षु श्री प्रेम प्रकाश साहू एवं विशिष्ट सहायक श्री वैभव पांडे ने किसानों को इफको के आधुनिक कृषि उत्पादों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर के प्रयोग की विधि, उपयोगिता तथा विभिन्न फसलों में इनके महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीक और नैनो उर्वरकों के उपयोग के संबंध में रुचिपूर्वक जानकारी प्राप्त की, जिससे उनमें खेती को अधिक वैज्ञानिक और उन्नत तरीके से करने के प्रति उत्साह दिखाई दिया।

सहकारी समिति गठन और संचालन की दी गई जानकारी

बस्तर जिला सहकारी संघ, जगदलपुर के प्रबंधक श्री सी.के. द्विवेदी ने सहकारी समितियों के पंजीयन, गठन एवं संचालन व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को सहकारिता के माध्यम से संगठित होकर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीणों के लिए उपयोगी : पोदिया राम

ग्राम सरपंच श्री पोदिया राम ने अपने संबोधन में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी को व्यवहार में उतारकर किसान अपनी कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को अधिक सशक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण कृषकों का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहकारिता, आधुनिक कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा जैविक खेती को एक-दूसरे से जोड़कर आय वृद्धि के नए अवसर विकसित करने की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

तेलीसेमरा की महिलाओं को दी गई सहकारी योजनाओं की जानकारी

- सहकारिता को बनाया आय एवं आत्मनिर्भरता का माध्यम
- महिलाओं को शासन की विभिन्न सहकारी योजनाओं और आंगनबाड़ी सेवाओं की दी गई जानकारी

जगदलपुर। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को सहकारिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा निरंतर सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 8 सितंबर को बस्तर संभाग के ग्राम तेलीसेमरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सामूहिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी दी गई।

सहकारिता से समृद्धि का संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को सहकारिता का उद्देश्य, महत्व एवं सहकारी संस्थाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से महिलाओं को मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए सहकारिता के माध्यम से गांवों में आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि लाने के विषय पर प्रकाश डाला गया।

महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने सहकारी योजनाओं एवं सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता के अवसरों को समझा तथा विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को केवल योजनाओं की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उन्हें संगठित होकर सहकारिता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना भी रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सुदन मौर्य का विशेष योगदान रहा। ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को सार्थक बनाया।

आंगनबाड़ी सेवाओं की भी दी गई जानकारी

कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कर्मचारी श्रीमती सुशीला चालकी ने महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों एवं माताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने, उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की मजबूत नींव तैयार करने तथा शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु एवं कुपोषण को दूर करने में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की निगरानी, देखभाल तथा माताओं को बच्चों के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी देने के संबंध में भी विस्तार से समझाया।

करपावंड की महिलाओं को मिला सहकारी प्रशिक्षण

- सहकारिता के सिद्धांतों से व्यवसाय विकास तक की दी गई जानकारी
- मछली, बकरी एवं गौ पालन से आय बढ़ाने पर जोर

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संभागीय कार्यालय, जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम करपावंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण प्रशिक्षक श्री मितेश पानीग्राही द्वारा प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण में महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य एवं विकास, सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, बैठकों, बैंक लिंकेज, पंजीयन एवं व्यवसाय विकास की जानकारी दी गई। साथ ही ÷सहकार से समृद्धि÷ की अवधारणा के तहत मछली पालन, बकरी पालन एवं गौ पालन को आयवृद्धि का माध्यम बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का विशेष सहयोग रहा।

डिजिटल छत्तीसगढ़ : अब ज़मीन के सीमांकन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर

- नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश,पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे। जिससे सीमांकन के ऑफ्लाइन या मैन्युअल आवेदन को E-Court अंतर्गत तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में ज़रूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।

सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील

नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी।

ई-गवर्नेंस की ओर एक और बड़ा कदम

राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित क्र-1 एवं P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की क्यूआर कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़मीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जा चुका है। राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक केएन कांडे सेवानिवृत्त, भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के प्रबंध संचालक श्री केएन कांडे के 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह 31 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय के सभागार में आयोजित किया गया।

समारोह में अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार गुप्ता ने श्री कांडे के दीर्घकालीन सेवाकाल और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि श्री कांडे ने सहकारी क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन, प्रशासनिक दक्षता और समन्वय के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री केएन कांडे ने जुलाई 2020 में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण किया था। उनके कार्यकाल में बैंक की वित्तीय एवं संस्थागत गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। बैंक की शेयर कैपिटल वर्ष 2020-21 में 160 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 246 करोड़ रुपये, रिजर्व फंड 389 करोड़ से बढ़कर 809 करोड़ रुपये तथा डिपॉजिट 5,550 करोड़ से बढ़कर 8,653 करोड़ रुपये हुआ। इसी अवधि में बैंक का कैपिटल लगभग 7,493 करोड़ से बढ़कर 11,901 करोड़ रुपये तक पहुंचा।

उनके कार्यकाल में प्रदेश के को-ऑपरेटिव बैंकों की शाखाओं की संख्या भी 302 से बढ़कर 345 हुई। साथ ही नवीन संवर्ग के 395 पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की नई शाखाएं भी प्रारंभ की गईं।

विदाई समारोह में अपर आयुक्त श्रीमती सावित्री भगत ने कहा कि श्री कांडे ने सहकारिता क्षेत्र में कुशल, व्यवहारिक एवं कर्मठ प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त संदीप गुप्ता ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों तथा पैक्स सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण में श्री कांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समारोह में अपेक्स बैंक की विभिन्न शाखाओं एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्री कांडे को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में श्री विनोद बुनकर, श्रीमती किरण गुप्ता, श्री मुकेश कुमार ध्रुव, श्री पी.सी. ध्रुव, श्री रजत किशोर सहित वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सहकारी शक्कर कारखानों के प्रबंध संचालक तथा अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान सहकर्मियों ने श्री कांडे को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया और उनके सेवाकाल के लिए आभार व्यक्त किया।

दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय में बदलें : निरंजन सिन्हा

- प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

कुरूद। छत्तीसगढ़ में पशुपालन की परंपरा लंबे समय से मुख्यतः घरेलू उपयोग तक सीमित रही है। आवश्यकता पूरी होने के बाद पशुओं को खुले में छोड़ देने की प्रवृत्ति को बदलते हुए पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। सहकारी बैंक पशुपालकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। हमें स्वयं दूध निकालना सीखने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक एवं गुजरात मॉडल की तर्ज पर दुग्ध सहकारिता को मजबूत करना होगा। गांवों को आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए जनता की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी रूप से मिल सकेगा।

उक्त विचार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा ने ग्राम पचपेड़ी स्थित समरसता भवन में आयोजित जिला स्तरीय प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की एकदिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में व्यक्त किए। कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी संघ, धमतरी द्वारा किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं केंद्र शासन की दुग्ध विकास संबंधी योजनाओं, उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का चयन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय, संतुलित एवं पोषक आहार, पशु शेड निर्माण तथा दुधारू पशुओं के लिए उपलब्ध सब्सिडी एवं अन्य योजनाओं की जानकारी देकर पशुपालकों में जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत कुरूद के उपाध्यक्ष श्री सतीश जैन ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत कुरूद श्री रामगोपाल देवांगन, अतिरिक्त उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं धमतरी डॉ. टी.आर. वर्मा, पशुधन विभाग के डॉ. भूपेंद्र सिन्हा, डॉ. राकेश सिन्हा, डॉ. पीयूष दुबे, जिला सहकारी संघ के प्रवक्ता डॉ. ए.एन. दीक्षित एवं प्राधिकृत अधिकारी श्री सी.पी. साहू उपस्थित रहे।

पशुपालन को व्यवसाय की दृष्टि से अपनाएं – डॉ. टी.आर. वर्मा

डॉ. टी.आर. वर्मा ने कहा कि पशुपालकों को पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए पशुओं को अपनी व्यावसायिक पूंजी मानना चाहिए। गांवों में चारागाह की भूमि का संरक्षण आवश्यक है तथा श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्येक पशुपालक को हरे चारे की खेती करनी होगी, क्योंकि केवल बाजार से पशु आहार खरीदकर दुग्ध व्यवसाय को लाभकारी बनाना कठिन है। उन्होंने कहा कि हरा चारा दुग्ध उत्पादन की लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं के आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर दूध उत्पादन प्रभावित होता है। उन्होंने दुग्ध समितियों में किसानों को नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं – डॉ. भूपेंद्र सिन्हा

डॉ. भूपेंद्र सिन्हा ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं के पालन को बढ़ावा देने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संतुलित पशु आहार के महत्व पर प्रकाश डाला।

सहकारिता से कमजोर उत्पादकों का आर्थिक सशक्तिकरण : डॉ. ए.एन. दीक्षित

डॉ. ए.एन. दीक्षित ने कहा कि सहकारिता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों के सशक्तिकरण एवं उत्थान का भरोसेमंद माध्यम है। सहकारी संगठन निर्धन एवं छोटे उत्पादकों को संगठित कर उन्हें व्यवसाय का स्वामी बनाता है और बाजार की शक्तियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अंतर्गत देशभर में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत एवं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से दुग्ध उत्पादन का बाजार सीमित एवं स्थानीय रहा है। दूध शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होने के कारण किसानों को कई बार अपना दूध कम कीमत पर बेचना पड़ता था। दुग्ध सहकारिता ने इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अमूल के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1946 में आनंद में स्थापित अमूल ने डेयरी सहकारिता को नई दिशा दी और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में यह मॉडल देश की श्वेत क्रांति का आधार बना। निश्चित एवं उचित मूल्य पर दूध की बिक्री से दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डॉ. दीक्षित ने बताया कि धमतरी जिले में 63 दुग्ध सहकारी समितियों से लगभग 30 हजार किसान जुड़े हैं तथा प्रतिदिन लगभग 10 हजार लीटर दूध का संग्रहण किया जाता है। किसानों को भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करते हुए आने वाले वर्षों में देश के दुग्ध उत्पादन को और अधिक बढ़ाने तथा भारत की वैश्विक दुग्ध अर्थव्यवस्था में भूमिका मजबूत करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में जिले के बड़ी संख्या में पशुपालक, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री ए.पी. गुप्ता ने किया।

आत्मनिर्भरता की नई मिसाल- खेतों से मशरूम उत्पादन तक मिथिला दीदी ने लिखी सफलता की नई कहानी

■ स्व-सहायता समूह के सहयोग से 1.5 लाख की पूंजी से शुरू किया काम, अब हर महीने कमा रही हैं 50 हजार रुपये

रायपुर। पारंपरिक कृषि पर निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ने वाली ग्रामीण महिलाओं की सूची में अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरीगांव की मिथिला नायक दीदी का नाम भी जुड़ गया है। अपनी कड़ी मेहनत, सूझबूझ और शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन के बदौलत मिथिला दीदी ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है।

सीमित आय से आर्थिक मजबूती की ओर

महिलाओं में आत्मनिर्भरता की जो लहर उठ रही हैए उसका एक प्रेरणादायक उदाहरण बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरीगांव की मिथिला नायक दीदी हैए जिनके लिए मशरूम उत्पादन की खेती वरदान साबित हुई है। शुरुआत में परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे घर का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। इस चुनौती से निपटने के लिए मिथिला दीदी ने अन्नपूर्णा स्व-सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सखी क्लस्टर संगठन, बुदेली के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ।

1 लाख 50 हजार रूपए की शुरुआती पूंजी से सफर का आगाज: मशरूम उत्पादन का व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्होंने सखी क्लस्टर संगठन से ऋण 1 लाख 20 हजार रूपए, अपनी व्यक्तिगत बचत से 30 हजार रूपए इस प्रकार कुल शुरुआती लागतरू 1 लाख 20 हजार रूपए से मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू की। शुरुआती दौर में यह कार्य नया था, लेकिन सीखने की ललक और निरंतर प्रयासों से जल्द ही मशरूम उत्पादन एक सफल आजीविका गतिविधि में बदल गया। शुरुआती दौर में तापमान नियंत्रण, मार्केटिंग और तकनीकी जानकारी की कमी जैसी कई समस्याएं सामने आई। लेकिन मिथिला दीदी ने प्रशिक्षण लेकर और आपसी सहयोग से इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया।

सुशासन नीति और बेहतर मॉनिटरिंग का परिणाम: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की सतत् मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँच रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के नए अवसर गढ़ रही हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारते हुए यह संदेश दे रही है कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।

हर माह 50 हजार रूपए की आय और प्रेरणादायक पहल

बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन के चलते स्थानीय बाजारों में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी। वर्तमान में मिथिला दीदी अपने घर से ही मशरूम उत्पादन कर स्थानीय बाजार में बेचती हैं और प्रतिमाह लगभग 50 हजार रूपए की आमदनी अर्जित कर रही हैं। उनकी यह सफलता आज क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है।

देवगढ़ की रुकमणी ने हुनर को बनाया रोजगार

■ सीमेंट से सजावटी सामान बनाकर बढ़ाई आमदनी

रायगढ़। देवगढ़ की रुकमणी ने हुनर को बनाया रोजगारकभी गृहिणी के रूप में परिवार संभालने वाली रुकमणी आज सीमेंट से मंदिर और सजावटी सामग्री तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने मेहनत और हुनर के दम पर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने समूह के माध्यम से बचत की और ऋण लेकर अपने हुनर को रोजगार का रूप दिया। आज इस काम से उन्हें हर महीने करीब 45 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है।

समूह की बचत और ऋण बना आर्थिक मजबूती का आधार

रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम देवगढ़ की रुकमणी कुंवर ने बिहान योजना के तहत गठित समूह से जुड़ीं। समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने नियमित बचत शुरू की। इसके बाद आरएफ, सीआईएफ और बैंक लोन के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सीमेंट से मंदिर एवं विभिन्न सजावटी वस्तुएं बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ काम करने वाली रुकमणी ने धीरे-धीरे अपने काम का विस्तार किया। वर्तमान में उन्होंने बैंक से करीब 50 हजार रुपये का ऋण लिया है, वहीं समूह से भी 20 हजार रुपये का ऋण लेकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया।

हुनर को बनाया कारोबार, परिवार की जरूरतें हो रहीं पूरी

रुकमणी सीमेंट से छोटे-बड़े मंदिर, घर की साज-सज्जा और पूजा-पाठ में उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुएं तैयार करती हैं। तैयार सामग्री को स्थानीय स्तर पर बेचकर उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। मेहनत, समूह का सहयोग और बिहान योजना से मिले आर्थिक संबल ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है। अब रुकमणी न केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक रूप से योगदान दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन रही हैं।

बिहान योजना से ग्रामीण महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

छत्तीसगढ़ शासन की बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने के साथ ही रोटेशनल फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक ऋण के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिलाएं पशुपालन, सिलाई, मसाला एवं अचार निर्माण सहित विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। स्थानीय हाट-बाजारों और सरस मेलों के माध्यम से महिला समूहों को अपने उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसान किताब और केसीसी कार्ड से सोहन सिंह की खेती-किसानी हुई आसान

■ खाद, बीज और कृषि सामग्री की खरीदी में मिल रही सुविधा, किसान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले में किसानों को किसान किताब एवं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सुविधा मिल रही है।

जशपुर जिले के ग्राम बरगांव डूमरटोली निवासी किसान श्री सोहन सिंह को किसान किताब के साथ केसीसी कार्ड प्राप्त हुआ है। किसान किताब और केसीसी कार्ड मिलने से उन्हें अब खेती के लिए खाद, बीज सहित अन्य आवश्यक कृषि सामग्री की खरीदी में सहूलियत हो रही है। इससे कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने में भी मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री साय के प्रति जताया आभार

किसान श्री सोहन सिंह ने किसान किताब एवं केसीसी कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसान किताब मिलने से खेती-किसानी से जुड़े कार्यों में काफी सुविधा हुई है। उन्होंने इसे किसानों के लिए उपयोगी पहल बताते हुए कहा कि इससे कृषि कार्यों

के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में आसानी हो रही है। किसान किताब और केसीसी कार्ड की सुविधा से श्री सोहन सिंह जैसे किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में सहूलियत मिल रही है। राज्य सरकार की यह पहल किसानों को कृषि कार्यों में सुविधा प्रदान करने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जीवामृत के उपयोग से धान की फसल में दिख रहा सकारात्मक प्रभाव

■ प्रदर्शन भ्रमण के माध्यम से किसानों को जैविक खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा प्रेरित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न ग्रामों में जीवामृत जैविक खाद के उपयोग से तैयार धान की फसल का प्रदर्शन भ्रमण कराया गया।

इन गांवों की फसल का कराया गया प्रदर्शन

जोगीसार, बढ़ावनडांड, भाड़ी, देवरी खुर्द एवं बारीउमराव ग्रामों में जीवामृत जैविक खाद का उपयोग कर तैयार की गई धान की फसल का प्रदर्शन उसी गांव के अन्य किसानों को कराया गया। प्रदर्शन के दौरान

किसानों ने जीवामृत के उपयोग से फसल में दिखाई दे रहे सकारात्मक प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। फसल की स्थिति एवं वृद्धि को देखकर अनेक किसान आश्चर्यचकित हुए और जैविक खाद के उपयोग के प्रति उनकी रुचि बढ़ी।

जैविक खाद है जीवामृत: किसानों को बताया गया कि, जीवामृत जैसे जैविक खाद के उपयोग से खेती में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। प्रदर्शन भ्रमण से प्रभावित होकर अन्य किसान भी स्वयं जीवामृत खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

अनुभव से दिया जा रहा प्रशिक्षण: जिले में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए खेतों में प्रदर्शन, कृषक भ्रमण एवं अनुभव साझा करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ते हुए स्वस्थ मृदा, बेहतर कृषि उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है।

सहकारिता कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। आर्थिक क्षमता प्राप्त करने के लिए समान कार्य और समान विचारधारा के लोग मिलकर 'एक के लिए सब और सबके लिए एक' की भावना के साथ कार्य करते हैं। सहकारिता सदस्यों की, सदस्यों द्वारा और सदस्यों के लिए संचालित व्यवस्था है।

सहकारिता क्या, क्यों और कैसे

सहकारिता कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है

भारत की आत्मा गांव, गरीब और किसान के बीच बसती है। भारत की आधी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। देश में समृद्धि के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या अभी भी अधिक है। भारतीय किसान आज भी वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। खेती में पर्याप्त संसाधनों के अभाव के साथ-साथ उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए क्रय शक्ति की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।

आज भारतीय कृषि को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से अनुदान एवं सहायता प्रदान कर किसानों को खेती से जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद उत्पादन को अपेक्षित स्तर तक ले जाना चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और सरकार का किसानों पर होने वाला व्यय भी लगातार बढ़ रहा है।

संगठन ही आर्थिक सशक्तिकरण का आधार

गांव, गरीब और किसानों के समूह को संगठित कर समृद्धशाली गांवों के निर्माण का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें संगठन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हों। गरीब संगठित होकर बड़े से बड़े उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हों और आर्थिक क्षमता प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार किसान संगठित होकर अपने कृषि उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता का बनाने तथा समूह के माध्यम से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास ही सहकारिता है।

विवेक पांडेय
जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर

सहकारिता का मूल भाव

सहकारिता चार अक्षर के शब्द सहकार से बना है–

स – सबका समाज

ह – हमारी व्यवस्था एवं हमारा प्रबंधन

क – कल्याणकारी कार्य

र – राजनीति से दूर

सबका समाज अर्थात जिस उद्देश्य के लिए समूह का उदय हुआ है, उस समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। समूह की व्यवस्था एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी समूह के लोगों की हो। समूह का प्रबंधन ऐसा हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सके तथा रोजगार सृजन के साथ आर्थिक क्षमता विकसित हो।

सहकारी संस्था में आने के बाद प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य संस्था की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए। सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सहकारी संस्था के भीतर सभी सदस्यों का लक्ष्य संस्था के हित एवं आर्थिक विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होना चाहिए। इसी कारण सहकारी संस्थाओं में राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाती है।

कानून और उपविधियों के आधार पर संचालन

भारत में सहकारिता को राज्य का विषय माना गया है। प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए पृथक कानून एवं नियम बनाता है। इन्हीं कानूनों, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार सहकारी संस्थाओं का गठन एवं संचालन किया जाता है।

सहकारी संस्था का गठन संबंधित सहकारी अधिनियम एवं उसकी उपविधियों के अनुरूप होता है। पंजीयन के बाद संस्था के सदस्य संस्था के वास्तविक स्वामी होते हैं। सदस्य उपविधियों में निर्धारित प्रवेश शुल्क, अंशपूंजी आदि के रूप में राशि संस्था में जमा करते हैं, जिससे संस्था की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

संस्था का संचालन सदस्यों द्वारा निर्वाचित समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसे संचालक मंडल कहा जाता है। सदस्यों द्वारा वार्षिक आमसभा में प्रस्ताव पारित कर संस्था के संचालन की जिम्मेदारी संचालक मंडल को सौंपी जाती है।

सदस्यों के हित और पारदर्शिता

संचालक मंडल द्वारा संस्था के संचालन के दौरान किसी भी सदस्य के हित प्रभावित न हों, इसके लिए संस्था के लेखों का संधारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संचालक मंडल की निगरानी में किया जाता है। संस्था के खातों का विधिवत अंकेक्षण सहकारिता विभाग के ऑडिट स्टाफ अथवा निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। इससे संस्था के सदस्यों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वास बना रहता है। यदि सहकारी संस्था जिस उद्देश्य से गठित की गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं होती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था का समापन भी किया जा सकता है।

एक के लिए सब और सबके लिए एक

सहकारिता ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बनाने वाली व्यवस्था के विपरीत गरीब और कमजोर वर्ग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा संचालित आंदोलन है। इसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को महत्व दिया जाता है। सहकारिता की मूल भावना एक के लिए सब और सबके लिए एक है। सामूहिक प्रयास, पारस्परिक सहयोग और विश्वास के माध्यम से ही सहकारिता आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का मजबूत आधार बन सकती है।

बिहान से बदली राह : 35 महिला किसानों ने 600 क्विंटल सब्जी उगाकर लिखी सफलता की नई कहानी

- **उजाला उत्पादक समूह की दीदियों ने सामूहिक खेती से हासिल की नई पहचान, सीधे थोक बिक्री से 6 लाख रूपए की आय**

रायपुर। पारंपरिक खेती से हटकर हरी सब्जियों की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती अपनाने वाले कई किसानों ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सफलता की नई कहानियां लिखी हैं, जिनमें ग्राम पंचायत रिसोरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ी महिलाओं ने सामूहिक खेती जैसी प्रेरणादायक मिसालें शामिल हैं, जो कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती थी और आज लाखों की कमाई कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रिसोरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ी महिलाओं ने सामूहिक खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। छोटे से भूखंड पर भी टमाटर, बैंगन, लौकी या करेला, खीरा जैसी सब्जियां उगाकर किसान प्रति बीघा या एकड़ कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उजाला उत्पादक समूह से जुड़ी 35 महिला किसानों ने एकजुट होकर न केवल लागत घटाई, बल्कि 600 क्विंटल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन कर करीब 6 लाख रूपए की आय अर्जित की है।

600 क्विंटल सब्जियों की बंपर पैदावार: महिलाओं की कड़ी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से खेतों में शानदार उत्पादन हुआ। सब्जी की फसल से बचत बढने लगी तो महिलाओं का हौसला बढ़ा। इसके साथ ही फसल का दायरा बढ़ाने लगी, जिससे पैदावार में बढ़ोत्तरी होने लगी। महिलाओं ने सामूहिक खेती कर लौकी 250 क्विंटल, करेला 250 क्विंटल, खीरा 100 क्विंटल का उत्पादन की। कुल सब्जी उत्पादन 600 क्विंटल होने लगा।

खेती का तरीका बदला तो बढ़ा उत्पादन और मुनाफा

- **राज कुमार साहू ने बरबट्टी और खीरा की खेती से कमाया 2.70 लाख रुपये का शुद्ध लाभ**

रायगढ़। कभी पारंपरिक तरीके से खेती कर सीमित लाभ प्राप्त करने वाले किसान राज कुमार साहू ने खेती में बदलाव और आधुनिक तकनीक अपनाकर बरबटी एवं खीरा की खेती से बेहतर उत्पादन प्राप्त किया। इससे उन्होंने 2.70 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। उनकी यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक बन रही है।

खरसिया विकासखंड के ग्राम बाम्हनपाली निवासी किसान राज कुमार साहू के पास 0.800 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। पहले वे पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिससे उन्हें लगभग 60 से 80 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता था। इससे करीब 2.48 लाख रुपये की बिक्री होती थी और लगभग 78 हजार रुपये का लाभ प्राप्त होता था। खेती में नई तकनीक और बेहतर फसल प्रबंधन अपनाने के बाद उनका उत्पादन बढ़कर 100 से 120 क्विंटल तक पहुंच गया। इससे उन्हें 3.60 लाख रुपये की बिक्री प्राप्त हुई, जबकि उत्पादन में 90 हजार रुपये की लागत आई। लागत राशि घटाने के बाद उन्हें 2.70 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह उनकी आय और लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

जैविक खाद और अनुशंसित दवाओं का ही उपयोग

राज कुमार साहू ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में फसल प्रबंधन किया तथा जैविक खाद एवं अनुशंसित दवाओं का उपयोग किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत उन्हें 20 हजार रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में शाखा प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

- **अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा के मार्गदर्शन में वित्तीय प्रबंधन एवं बैंकिंग कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण**

रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर में 11 सितंबर 2026 को शाखा प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए वर्कशॉप कम ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शाखाओं में वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता को और बेहतर करना रहा।

वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन पर विशेष प्रशिक्षण : प्रशिक्षण के दौरान क्रेडिट एवं डेबिट एंट्री, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, सकल एवं शुद्ध लाभ की गणना, प्रावधान एवं रिजर्व, उपार्जित व्यय, सॉल्वेंसी एवं लिक्विडिटी तथा अकाउंट्स एवं स्टेटमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। ऋण, सुरक्षा एवं पूंजी संबंधी विषयों पर मार्गदर्शनः कार्यक्रम में चार्ज, प्लेज, हाइपोथिकेशन एवं मॉर्गेज, ओन्ड फंड/नेटवर्थ, बॉरोड फंड, वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू एवं फंड, कवरेज एवं लीवरेज, रिजर्व फंड, एक्सपोजर लिमिट, टर्नओवर तथा लोन एवं एडवांस से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

चेक, अकाउंटिंग एवं बैंकिंग नियमों की जानकारी : शाखा प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों को चेक डिसऑनर एवं चेक बाउंस, बुक कीपिंग एवं अकाउंटेंसी, गुड्स एवं एसेट्स, एक्सपेंसेस एवं एसेट्स, पर्सनल/रियल/नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट एवं बजट सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई।

बैंकिंग दरों, एनपीए एवं सीआरएआर पर चर्चा

प्रशिक्षण में प्राइम लेंडिंग रेट, रेपो रेट एवं बैंक रेट, सब्सिडी एवं सबवेंशन, सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों में अंतर, एनपीए, सी.डी. रेशियो , सीआरएआर , इंडेम्निटी एवं प्रॉमिसरी नोट तथा बैंकिंग विनियमों के विकास जैसे विषयों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता पर जोर

कार्यक्रम में बैंक की शाखाओं में वित्तीय अनुशासन, लेखांकन की शुद्धता, ऋण एवं अग्रिमों की प्रभावी निगरानी, बैंकिंग नियमों का पालन तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों एवं आधुनिक वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप अधिक दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इनकी रही प्रमुख उपस्थिति

इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अपेक्षा व्यास, श्री एस.पी. चंद्राकर , श्री डी.के. व्यास, श्री आई.के. ठाकुर , श्री प्रदीप सोनी, श्री संजीव दीवान एवं श्री रामनारायण यादव सहित विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शाखा स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करते हुए बैंक की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं दक्ष बनाना रहा।

खेत बना आय का केंद्र, नवाचार ने बदली खेती की तस्वीर

युवा किसान अंकित लकड़ा ने मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी को जोड़कर तैयार किया एकीकृत कृषि मॉडल

■ **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिली 8 लाख रुपये की अनुदान सहायता, दो तालाबों में मछली पालन के साथ 1,000 से 1,200 मुर्गियों का कर रहे पालन**

रायपुर। खेती में बदलाव केवल नई तकनीक से नहीं, बल्कि नई सोच से भी आता है। जशपुर जिले के ग्राम रतबा के युवा किसान अंकित लकड़ा ने इस बात को अपनी मेहनत और नवाचार से साबित किया है। कभी केवल बारिश के भरोसे धान की खेती करने वाले अंकित ने आज अपने खेत को मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और बहुफसली खेती से जोड़कर आय के कई स्रोत तैयार कर लिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय के अवसर बढ़ाने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अंकित को भी मिला है। योजनाओं से मिली सहायता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने पारंपरिक खेती को आधुनिक और बहुआयामी कृषि मॉडल में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

धान की खेती से शुरू हुआ सफर, अब खेत में कई गतिविधियां

अंकित लकड़ा बताते हैं कि पहले वे मुख्य रूप से बरसात के मौसम में धान की खेती करते थे। खेती से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कृषि और मत्स्य विभाग से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपने खेत में दो तालाब तैयार कराए और मछली पालन शुरू किया। तालाब बनने के बाद उनके खेत की तस्वीर ही बदल गई। तालाब के पानी का उपयोग गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए होने लगा। इससे वे अब वर्षा ऋतु के अलावा गर्मी में भी खेती कर पा रहे हैं। साथ ही खेत में आम और लीची सहित विभिन्न फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिससे आने वाले समय में बागवानी भी उनकी अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी।

एक ही संसाधन से मछली और मुर्गी पालन का नवाचार

अंकित ने अपने दोनों तालाबों के ऊपर मुर्गी पालन के लिए शेड तैयार किया है। शेड की क्षमता करीब 1,000 से 1,200 मुर्गियों की है। उन्होंने मुर्गी पालन और मछली पालन को आपस में जोड़कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का तरीका अपनाया है। मुर्गियों से निकलने वाला अपशिष्ट तालाब में पहुंचकर मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार के रूप में उपयोगी होता है। इससे मछली पालन में बाहरी आहार पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिलती है। इस तरह एक ही स्थान पर संचालित दो गतिविधियां एक-दूसरे को सहारा देती हैं और किसान को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराती हैं।

युवाओं के लिए खेती बना रहे हैं आकर्षक विकल्प

अंकित लकड़ा की कहानी उन ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेती को केवल पारंपरिक रीति से करने के बजाय इसे आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। उनका अनुभव बताता है कि उपलब्ध भूमि और पानी जैसे संसाधनों का बेहतर नियोजन, शासकीय योजनाओं की जानकारी और मेहनत के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। अंकित की पहल यह संदेश देती है कि खेती में नवाचार, योजनाओं का सही उपयोग और विभिन्न कृषि गतिविधियों का समन्वय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकता है। उनका खेत अब सिर्फ फसल उत्पादन की जगह नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरक मिसाल बन गया है।

तालाब की मेड़ पर फलदार पौधे, दोहरा लाभ

अंकित ने तालाब की मेड़ों पर आम सहित अन्य फलदार पौधे भी लगाए हैं। तालाब के पानी से इन पौधों की सिंचाई की जाती है। उनका कहना है कि मेड़ पर पेड़ लगाने से मिट्टी को मजबूती मिलती है और मेड़ के कटाव को रोकने में भी मदद मिलती है। वहीं आम और लीची जैसे फलदार पौधे भविष्य में अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेंगे। इस प्रकार अंकित ने खेत के प्रत्येक हिस्से का उपयोग उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए किया है। तालाब उनके लिए केवल मछली पालन का साधन नहीं, बल्कि सिंचाई, बागवानी और मुर्गी पालन से जुड़ी गतिविधियों का आधार बन गया है।

8 लाख रुपये की अनुदान सहायता से मिला नवाचार को विस्तार: अंकित को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए शासकीय सहायता मिली। मत्स्य विभाग से उन्हें करीब 8 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इसके साथ पॉन्ड लाइनर, पॉलीथिन, बोर, मोटर और मछली आहार जैसी आवश्यक सामग्री की सुविधा भी मिली। शासकीय योजना से मिली सहायता ने उनके लिए मछली पालन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता आसान किया। अंकित बताते हैं कि विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी और मार्गदर्शन से उन्हें आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करने में काफी मदद मिली।

बहुफसली खेती से बढ़े आमदनी के अवसर: अंकित अब अपने खेत को केवल एक फसल तक सीमित नहीं रखते। मछली पालन और मुर्गी पालन के साथ वे अलग-अलग मौसम में विभिन्न फसलों की खेती और बागवानी कर रहे हैं। तालाब के पानी की उपलब्धता ने उन्हें गर्मी में भी खेती करने का अवसर दिया है। इस बहुआयामी मॉडल से उन्हें सालभर अपने खेत से उत्पादन प्राप्त करने और आय के अलग-अलग स्रोत विकसित करने का अवसर मिल रहा है। उनके खेत में कृषि के साथ पशु एवं मत्स्य आधारित गतिविधियों का समन्वय ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली की उपयोगिता को भी दर्शाता है।

बंजर जमीन पर लहलहाई ग्राफ्टेड बैंगन की फसल

■ **रायगढ़ के किसान ने ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की खेती से कमाए 4.25 लाख**

रायपुर। ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की खेती (जिसमें नीचे जंगली बैंगन यानी रूटस्टॉक और ऊपर टमाटर या हाइब्रिड बैंगन यानी सायन होता है) पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक फायदेमंद और रोग-प्रतिरोधी है। यह पौधा अधिक पानी या लंबे समय तक सूखा और भारी बारिश को आसानी से सहन कर लेता है।

ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की खेती 4.25 लाख की आमदनी भी अर्जित की

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम झारआमा के किसान श्री एतवार साय पैकरा ने आधुनिक तकनीक और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से खेती में सफलता की नई मिसाल कायम की है। कभी अनुपयोगी और बंजर पड़ी रहने वाली जमीन पर ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की खेती कर उन्होंने न केवल 187 क्विंटल का बंपर उत्पादन हासिल किया, बल्कि कुल 4.25 लाख की आमदनी भी अर्जित की।

तकनीक और सही मार्गदर्शन से मिली सफलता

किसान की जमीन गांव से दूर जंगल के समीप स्थित होने और सिंचाई साधनों के अभाव के कारण वहां खेती करना आसान नहीं था। उद्यानिकी विभाग की सलाह पर उन्होंने भूमि का समतलीकरण कराया और सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक एवं मल्चिंग पद्धतियों को अपनाया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 में उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड सब्जियों की बुआई की।

उत्पादन और आय का गणित

टमाटर फसल 87 क्विंटल उत्पादन कर 1 लाख 75 हजार रूपए की बिक्री की। इसी प्रकार बैंगन फसल 100 क्विंटल उत्पादन कर 2 लाख 50 हजार रूपए की बिक्री की। कुल उत्पादन व बिक्री 187 क्विंटल 4 लाख 2 5 हजार रूपए की बिक्री की। किसान को कुल लागत 1 लाख 45 हजार रूपए लगा जबकि शुद्ध लाभ 2 लाख 80 हजार रूपए का हुआ।

बलरामपुर जिले के 6 हजार 968 परिवारों को मिला अपना पक्का आशियाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में ग्रामीण विकास और आवासहीन जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल 2026 से अब तक पूर्ण हुए कुल 6 हजार 968 नवनिर्मित आवासों का भव्य एवं सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम 11 सितंबर 2026 को पूरे जिले में बेहद उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान से पहले हजारों परिवारों का अपने पक्के घर में प्रवेश करना जिले के लिए एक विशेष उपलब्धि बन गया है।

'परंपरागत रीति-रिवाज के साथ सौंपी गई चाबियां'- बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सभी विकासखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूजा-अर्चना के साथ हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। वर्षों तक कच्चे मकानों और झोपड़ियों में जीवन बिताने वाले परिवारों के लिए यह पल बेहद भावुक और गौरव से भरा हुआ था।

'विकासखंडवार पूर्ण हुए आवासों की स्थिति'- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विकासखंड रामचन्द्रपुर में 2,276 आवास, विकासखंड वाड्रफनगर 1 हजार 772 आवास, विकासखंड कुसमी 1 हजार 215 आवास, विकासखंड बलरामपुर 1 हजार 142 आवास, विकासखंड राजपुर 353 आवास और विकासखंड शंकरगढ़ 210 पक्का आवास पूर्ण कराए गए हैं।

महिलाओं को राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी प्रशिक्षण

■ **सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरव शर्मा के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी केंद्र अटपरी सेमरा में महिलाओं के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा ने महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, आत्मनिर्भर बनने तथा सामूहिक रूप से रोजगार प्राप्त करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नई सहकारी समिति के पंजीयन की प्रक्रिया एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारी श्रीमती रुक्मणी मौर्य ने महिलाओं को पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने महिलाओं को बच्चों एवं परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण तथा नियमित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सूदन मौर्य का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सहकारिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
- खामभाठा में निर्माणाधीन पुल से बच्चों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश में जनसुविधा से जुड़े विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों की नियमित निगरानी करें और जहां भी कार्य की गति धीमी है, वहां बाधाओं को तत्काल दूर कर काम में तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। विशेष रूप से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में लेटलतीफी को गंभीरता से लिया जाएगा और अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत खामभाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी मिलते ही इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने गरियाबंद कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा से दूरभाष पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और निश्चित समयसीमा तय कर पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लेटलतीफी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण पूरा होने तक स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों को किसी भी परिस्थिति में जोखिम उठाकर आवागमन न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन तत्काल सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्माणाधीन पुल स्थल पर सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने खुले एवं खतरनाक तरीके से लगे सरियों को सुरक्षित करने, गहरे गड्ढों और अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों को दुरुस्त करने तथा आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग सहित सभी जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण में आ रही बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए और कार्य में तेजी लाई जाए। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत विकास कार्यों का लाभ नागरिकों को निर्धारित समय पर मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

महतारी वंदन का संबल : आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही विमला यादव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में संचालित महतारी वंदन योजना परिवारों के लिए निरंतर आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे वे अपनी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ आर्थिक निर्णयों में भी अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं।

अम्बिकापुर के बोरीपारा, शिकारी रोड निवासी विमला यादव भी महतारी वंदन योजना की नियमित हितग्राही हैं। हर महीने उनके बैंक खाते में मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि ने उन्हें अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा दिया है। विमला बताती हैं कि योजना की राशि से कभी बच्चों की स्कूल और कोचिंग फीस जमा करती हैं, तो कभी घर के लिए राशन खरीदती हैं। आवश्यकता पड़ने

पर इसी राशि का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी किया जाता है।

विमला यादव के लिए महतारी वंदन योजना की राशि केवल एक निश्चित आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जरूरत के समय मिलने वाला भरोसेमंद सहारा है। सीमित आय वाले परिवारों में अचानक सामने आने वाले छोटे-छोटे खर्च कई बार परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसे समय में हर माह खाते में आने वाली राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च हो, घर के राशन की जरूरत हो या दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर खर्चकृविमला अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग कर रही हैं। उनका कहना है कि अब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और उनमें अपने खर्चों को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा है।

परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से विमला यादव ने एक छोटी किराना दुकान भी शुरू की है। वे स्वयं दुकान का संचालन करती हैं और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। विमला बताती हैं कि पहले छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें पति से पैसे मांगने पड़ते थे और कई बार अपनी आवश्यकताओं को टालना पड़ता था। अब हर माह स्वयं के बैंक खाते में राशि आने से उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम महसूस होता है।

हल्दी की खेती से बढ़ रही फसल विविधता, किसानों की आय में हो रही वृद्धि

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ फसल विविधता को भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है। उद्यानिकी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिलने से किसान अब पारंपरिक साग-सब्जी और फल उत्पादन के साथ मसाला फसलों की खेती में भी रुचि लेने लगे हैं। इससे प्रदेश में मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार होने के साथ किसानों के लिए आय के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

इसी दिशा में वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा योजना के तहत हल्दी फसल के क्षेत्र विस्तार के लिए 1300 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 620 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से किसानों को मसाला फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फसल विविधीकरण को गति मिल रही है। योजना के क्रियान्वयन से किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ हल्दी जैसी मसाला फसलों की खेती का विकल्प मिल रहा है। इससे एक ओर किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मसाला फसलों के उत्पादन में वृद्धि से स्थानीय स्तर पर उपलब्धता बढ़ेगी। हल्दी बीज की आपूर्ति को लेकर प्रसारित की जा रही भ्रामक जानकारियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उद्यानिकी विभाग ने बताया है कि हल्दी बीज की आपूर्ति संचालनालय एवं जिला स्तर से नही की जाती है अपितु छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को योजना अंतर्गत अनुदान का लाभ दिया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आईजीकेवी को 'ए ग्रेड' के साथ दी अधिमान्यता

- कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों से मिली यह महत्वपूर्ण उपलब्धि
- कृषि मंत्री नेताम ने कुलपति डॉ. चंदेल को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए दी बधाई

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए छत्तीसगढ़ को गौरवांवित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा अधिमान्यता बोर्ड द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा उसके अंतर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों एवं शिक्षण कार्यक्रमों को अधिमान्यता प्रदान करते हुए 'ए ग्रेड' दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल में ही विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को अधिमान्यता प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न महाविद्यालयों एवं शिक्षण कार्यक्रमों (स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों) को वर्ष मार्च 2024 से मार्च 2029 तक अवधि के लिए 'ए ग्रेड' के साथ अधिमान्यता प्रदान की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश के उत्कृष्ट कृषि विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विगत चार वर्षों में शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय

प्रयासों के कारण यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

साल 2019 में मिला था 'बी ग्रेड'

उल्लेखनीय है कि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2019 में जारी अधिमान्यता सूची में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 'बी ग्रेड' प्राप्त हुआ था। यहां यह भी बताना लाजमी होगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को विगत वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग में भी 28वां स्थान प्राप्त हुआ था तथा यह एनआईआरएफ रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं उनके समस्त सहयोगियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

ए ग्रेड प्राप्त होने से होंगे अनेक लाभ

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त होने से अनेक लाभ होंगे। विश्वविद्यालय की साख में वृद्धि होगी। 'ए ग्रेड' मिलने से यह सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय ने शिक्षण, अनुसंधान, अधोसंरचना निर्माण, प्रशासन, छात्र सहायता आदि क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है। नवीन शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को उनके परफार्मेंस अर्थात ग्रेड के आधार पर विभिन्न अधोसंरचनाओं (महाविद्यालय भवन, हॉस्टल, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल मैदान आदि) के निर्माण एवं शिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अतः ग्रेड में वृद्धि से विश्वविद्यालय को भारत सरकार के विभिन्न विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकार तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं से शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा।

बढ़ेगी विश्वविद्यालय की साख

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की साख बढ़ेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अच्छे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित होंगे। अन्य विश्वविद्यालयों एवं विदेशी संस्थानों के साथ शिक्षण एवं शोध हेतु सहयोग में बढ़ोतरी होगी। कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार एवं औद्योगिक सहयोग में इजाफा होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जिन बिंदुओं के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालय को ग्रेड प्रदान की गई है उनमें शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अधोसंरचनाओं की उपलब्धता, शोध एवं अनुसंधान का स्तर, किसानों तक तकनीकों का हस्तांतरण, नवाचार, विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की स्थिति आदि प्रमुख है। ग्रेडिंग के दौरान विश्वविद्यालय एवं विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, क्लासरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, हॉस्टल सुविधा, प्लेग्राऊंड, फर्नीचर, आदि की उपलब्धता का भी ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही छात्र प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अध्यापन का स्तर, एकेडेमिक रेगुलेशन, मूल्यांकन, स्कॉलरशिप, छात्र कल्याण, संस्थागत डाटाबेस, आदि पर भी ध्यान दिया गया था।

सहकार भारती ने शहरी निगमों के लिए भविष्य के अनुकूल मांगे आदर्श उपनियम

- माधव दास समिति की 45 साल पुरानी रिपोर्ट पर आधारित मौजूदा उपनियम : जोशी

नई दिल्ली। सहकार भारती ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए आदर्श उपनियमों पर गठित समिति से एक प्रगतिशील और सक्षम नियामक ढांचा तैयार करने का आग्रह किया है जो इस क्षेत्र को उभरती बैंकिंग और तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार कर सके।

सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी ने आरबीआई समिति के अध्यक्ष दिनेश औलकर और उसके सदस्यों को संबोधित एक पत्र में, असंरक्षित सरकारी उपक्रमों (यूसीबी) के लिए आदर्श उपनियमों का मसौदा तैयार करने के आरबीआई के नए सिरे से किए जा रहे प्रयास का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा उपनियम काफी हद तक माधव दास समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो लगभग 45 साल पहले लागू हुई थी।

नए सिरे से मसौदा तैयार करना आवश्यक

जोशी ने बताया कि, दशकों से यूसीबी (शहरी केंद्रीय बैंकों) के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, वहीं बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और आरबीआई के मास्टर निर्देशों के माध्यम से किए गए परिवर्तनों ने नियामक वातावरण को और भी बदल दिया है। उन्होंने कहा कि, इससे उपनियमों की व्यापक समीक्षा और नए सिरे से मसौदा तैयार करना आवश्यक हो गया है। सहकार भारती ने शहरी सहकारी बैंकों के मुख्यधारा के बैंकिंग क्षेत्र के साथ क्रमिक एकीकरण का भी स्वागत किया और कहा कि, इस कदम से शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती मिल सकती है और वे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे।

दिया गया यह प्रस्ताव

सहकार भारती ने आगे प्रस्ताव दिया है कि, यूसीबी (शहरी केंद्रीय बैंकों) को पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करने का अधिकार दिया जाए, साथ ही ऐसी संस्थाओं को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की संभावना भी हो। इसने यह भी सुझाव दिया है कि किसी व्यक्ति या कानूनी इकाई की अधिकतम शेयरधारिता को बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी के प्रतिशत से जोड़ा जाए। पूंजी जुटाने के संबंध में, संगठन ने यूसीबी को म्यूचुअल फंड, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ट्रस्टों से शेयर पूंजी योगदान स्वीकार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। इसने यूसीबी को विभिन्न परिपक्वता अवधि और संरचनाओं के रेटेड बॉन्ड, साथ ही साथ रेटेड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर जारी करने की अनुमति भी मांगी है, ताकि अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लिए धन जुटाया जा सके। सहकार भारती ने सिफारिश की है कि अर्ध-शहरी और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग वैन संचालित करने के अलावा, यूसीबी को धन प्रबंधन, न्यास और व्यापारी बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

प्रमुख सुझावों में यह भी

सहकार भारती ने अपने प्रमुख सुझावों में से एक यह भी दिया है कि, यूसीबी बैंकों के लिए प्रतिनिधि सभाएं गठित करने का प्रावधान किया जाए, विशेषकर इसलिए क्योंकि कई बैंकों के हजारों या लाखों शेयरधारक हैं। इसने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यूसीबी बैंकों के चुनाव और बैठकें हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित करने की अनुमति दी जाए ताकि भागीदारी और सुलभता में सुधार हो सके। संगठन ने यूसीबी (यूसीबी) के संचालन क्षेत्र में अधिक लचीलेपन की मांग की है, जिसमें किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सटे जिले में मुख्यालय या शाखाएं रखने वाले बैंकों को पड़ोसी जिले में परिचालन का विस्तार करने की अनुमति शामिल है।

अधिक स्वायत्तता की मांग

पत्र में संगठनात्मक संरचना, भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और तबादलों सहित मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता की मांग की गई है। अंत में, इसमें आरबीआई से आग्रह किया गया है कि वह गैर-सरकारी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों को अपनाने और उन्नत करने में सक्षम बनाए। सहकार भारती ने इस बात पर जोर दिया कि, उसके अधिकांश प्रस्ताव प्रकृति में सहायक हैं और यूसीबी आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं।

को-ऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही में लाएं तेजी : केदार कश्यप

- सहकारिता मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा
- मंत्री श्री कश्यप ने सहकारी सप्ताह 2026 पर आधारित काफी-टेबल बुकलेट का किया विमोचन

रायपुर। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मंत्री श्री केदार कश्यप ने बैठक में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए कहा कि, राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

को-ऑपरेटिव सेक्टर पर केन्द्रित काफी-टेबल बुकलेट का विमोचन

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा। उन्होंने को-आपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की समीक्षा की। उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने सहकारी सप्ताह 29 जून से 06 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव सेक्टर में आयोजित विविध कार्यक्रम पर केन्द्रीत काफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया गया।

पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और ऑडिट प्रक्रिया में लाएं तेज़ी : बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित

मंत्री श्री कश्यप ने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से चालू खरीफसीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री श्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया। ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

718 गोदामों का निर्माण पूर्ण

मंत्री श्री कश्यप ने 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण व त्वथ् योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में आराईडीएफअंतर्गत आबंटित 725 गोदामों में 718 गोदामों के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष 7 गोदाम के जल्द ही निर्माण पूर्ण किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

शासकीय योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के आदेश दिए गए। बैठक के अंत में मंत्री श्री कश्यप ने सभी विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिये।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ सी.आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता व पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक श्री युगल किशोर, अपर पंजीयक श्री यू बीएस राठिया, अपर पंजीयक श्रीमती सावित्री भगत व सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के अधिकारीगण तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित थे।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफसेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail- cgcoopnews@gmail.com